# बिहार विधान परिषद्

## 189वां सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

## वर्ग – 2

**मंगलवार, तिथि** 02 श्रावण, 1940 (श.)
24 जुलाई, 2018 ई.

**प्रश्नों की कुल संख्या – 13**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | उद्योग विभाग | - | - | 02 |
| 2. | स्वास्थ्य विभाग | - | - | 08 |
| 3. | विधि विभाग | - | - | 01 |
| 4. | ऊर्जा विभाग | - | - | 02 |
| | | | कुल योग – | 13 |

## रोजगार मुहैया

16. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और इस हालात में बेरोजगार इंजीनियर डिग्रीधारी राज्य के +2 विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के पद पर भी आवेदन देने के लिए विवश हैं जबकि वे अच्छे उद्यमी बन सकते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया था और उनके साथ साझा समझौता भी हुआ था लेकिन अबतक उद्योग जमीनी स्तर में उतर नहीं सका है जिससे बेरोजगारों में हताशा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि राज्य में कब तक विविध उद्योग स्थापित करने एवं शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

---

## जागरूकता लाना

17. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अस्वास्थ्यकर भोजन (जंक फूड) का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके हानिकारक प्रभाव से दूर रहने हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से जारूकता लाना चाहती है, नहीं तो क्यों?

---

## ट्रामा सेन्टर का निर्माण

18. **श्री सोने लाल मेहता** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय से होकर पटना-बख्तियारपुर-बरौनी-बेगूसराय को जोड़नेवाला राजपथ-31 ही खगड़िया-पूर्णियां के रास्ते असम राज्य को जोड़नेवाला राजपथ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त राजपथ एवं उसके सम्पर्क पथों पर छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन का भारी दबाव रहने के कारण आवागमन के क्रम में भयंकर अप्रिय दुर्घटनाएं होती रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथों पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले मरीजों के लिए खगड़िया सदर अस्पताल, खगड़िया जिला के प्रखण्डवार स्वास्थ्य उपकेन्द्र या रेफरल अस्पताल, गोगरी में चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं रहने के कारण उसमें मात्र प्राथमिक उपचार हो पाता है;

(घ) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग और खगड़िया जिला प्रशासन के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध रहने पर भी आज तक खगड़िया जिला मुख्यालय में ट्रामा सेंटर नहीं बनने से आम नागरिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में नीति आयोग के सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत देश स्तर पर 110वें स्थान पर और बिहार राज्य स्तर पर 13वें स्थान पर आनेवाले खगड़िया जिला के खगड़िया जिला मुख्यालय में चिकित्सा व्यवस्था से लैस एक 'ट्रामा सेन्टर' खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा

19. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में लगभग 14 लाख पेंशनधारी कर्मचारी हैं जिन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात एवं अन्य राज्यों में पेंशनधारी कर्मचारी को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि पेंशनधारियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने सत्र 1988 में नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक संबंधित नियमावली नहीं बनी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के वंचित पेंशनधारियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## जांच फीस निर्धारित

20. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत 11 हजार 373 डाक्टरों के पद सृजित हैं, इनमें सामान्य चिकित्सक के 7843 व विशेषज्ञ डॉक्टर में 3526 पद हैं लेकिन करीब तीन हजार डाक्टर ही तैनात हैं, शेष लगभग 75 प्रतिशत पद रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में मानक के अनुसार डॉक्टर नहीं हैं, 30 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सदर अस्पताल से 194 डॉक्टर चार वर्ष से अधिक समय से गायब हैं, इनकी अनुपस्थिति की सूचना भी विभाग के पास नहीं है, वे विभाग को बिना कोई आवेदन दिये ही वर्षों से अस्पताल से गायब हैं, कई चिकित्सक किसी शहर में निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं;

(घ) क्या यह सही है कि निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिकित्सक फीस और जांच की फीस निर्धारित नहीं रहने के कारण राज्य में चिकित्सक मनमानी पैसा गरीब मरीजों से वसूल रहे हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी अस्पतालों में चिकित्सक बहाल एवं निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चिकित्सकों की फीस एवं जांच की फीस सरकार निर्धारित करना चाहती है, ताकि चिकित्सकों को मनमानी पैसा लेने से रोका जा सके?

---

## सेवा नियमितीकरण

21. **श्री मो. तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-3/एम.19/2015 सा.प्र.6161 (पटना, दिनांक 24.04.2015) द्वारा संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि शुरुआत में इस समिति को 3 माह में रिपोर्ट तैयार करने की जवाबदेही दी गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि उच्च स्तरीय समिति ने तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविदा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करना चाहती है, यदि हो तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

**पी.एच.सी. की स्थापना**

22. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखंड की थुम्हा पंचायत, जिसकी आबादी लगभग बीस हजार है, में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि इस पंचायत के आसपास की भी एक बड़ी आबादी को पी.एच.सी. उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को भयंकर तकलीफ हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि थुम्हा पंचायत में पी.एच.सी. स्थापना का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिशीघ्र थुम्हा पंचायत के थुम्हा गांव में पी.एच.सी. स्थापना कर जनता को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

---

**मुआवजा देने पर विचार**

23. **श्री राम ईश्वर महतो** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-मेटुआ, पं.-डोरपुर के एक किसान द्वारा ग्राम-मझौर में स्थित अपने मक्के की खेती को सुरक्षित रखने के लिए अमानवीय तरीके से बिजली के तार द्वारा चारों तरफ से घेर कर बिजली के पोल से कनेक्ट कर दिया था;

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम-मझौर, ग्राम-नानपुर के सुनील कुमार, उम्र-11 वर्ष, पिता-रघुवीर सिंह उसी रास्ते से जाने के क्रम में बिजली के तार में सटने के कारण घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे लोगों पर कौनी-सी कार्रवाई करना चाहती है, जिन्होंने बिजली के तार से घेर कर उस तार में विद्युत आपूर्ति कर दी जिसकी चपेट में आकर स्व. सुनील कुमार, पिता-रघुवीर सिंह, ग्राम-मझौर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी की इस अप्रिय घटना से मृत्यु हो गई, साथ ही साथ उस पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक?

---

**पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स**

24. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर वर्ष 1983 में पटना में स्थापित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एम्स, नई दिल्ली की तरह दन्त चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अबतक प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में उक्त कोर्स को कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है;

---

**बंद होने का कारण**

25. **श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 तक बिहार सरकार के निदेश पर समाचार पत्रों में बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा यह प्रकाशित कराना बाध्यता थी कि उसे कितनी-कितनी बिजली किस सोर्स से प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में होल्डिंग कम्पनी (पहले बिहार राज्य विद्युत पर्षद) द्वारा कितनी-कितनी बिजली किस सोर्स से ली जा रही है, यह व्यवस्था वर्ष 2010 के पश्चात बंद कर दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बताना चाहेगी कि इसके बंद करने के पीछे क्या कारण है, इसे जनहित में फिर से शुरू कराना चाहती है?

---

## रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार

26. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विगत आठ दशकों से चलने वाली मेसर्स रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर (प्रो. विन्सम इंटरनेशनल लिमिटेड) को सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रबंधन द्वारा 6 जुलाई 2017 को पूर्णत: बंद कर दिया है, जिस कारण लगभग बीस हजार बिहार के मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मजदूरों द्वारा लिए गए लोन पर प्रबंधन द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। दूसरी तरफ मजदूरों का उपादान एवं बोनस की बकाया राशि का भुगतान वर्षों से नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेराजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है एवं उक्त मिल को चालू करने एवं मजदूरों को दोहन से बचाने का कोई उपाय करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## महिला चिकित्सक की नियुक्ति

27. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिला के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर महिलाओं की आबादी 18,49,225 है;

(ख) क्या यह सही है कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गया जिला में प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25 है, लेकिन महिला चिकित्सक केवल चार हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकतर स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक नहीं रहने के कारण यहां की महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया जिला के सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## ड्रेसरों की नियुक्ति

28. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्रेसर के लगभग 1950 पद स्वीकृत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रा. स्वा. केन्द्र और मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक में ड्रेसर की घोर कमी है, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई और ड्रेसर की संख्या घटती गई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ड्रेसरों की नियुक्ति शीघ्र कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

---

**सुनील कुमार पंवार**
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 24 जुलाई, 2018